<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

संसद का शीतकालीन सत्र, 2011 (पंद्रहवीं लोक सभा का 9वां सत्र और राज्य सभा का 224वां सत्र) मंगलवार, 22 नवंबर, 2011 से आरंभ होना नियत है और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए यह सत्र बुधवार, 21 दिसंबर, 2011 को समाप्त होगा। सत्र की 30 दिनों की अवधि में 21 बैठकें होंगी।

2. सत्र में मुख्य रूप से आवश्यक सरकारी विधायी और अन्य कार्य निपटाया जाएगा जिसमें सामान्य बजट और रेल बजट के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों से संबंधित वित्तीय कार्य शामिल होगा।

3. शीतकालीन सत्र, 2011 के लिए सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्री ने सोमवार, 14 नवंबर, 2011 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बैठक की सह-अध्यक्षता की थी। पंद्रहवीं लोक सभा के 9वें सत्र और राज्य सभा के 224वें सत्र के दौरान लिए जाने वाले संभावित कार्य निम्न प्रकार से है:-

I. विचार और पारित करने के लिए विधेयक

क्र.सं.	विधेयकों के नाम
1.	लोकपाल विधेयक, 2011 *सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना से संबंधित विधान को लागू करना*
2.	सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010 *किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार या जानबूझकर शक्तियों के दुरूपयोग या जानबूझकर स्वनिर्णय के दुरूपयोग के किसी आरोप के प्रकटीकरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और ऐसे प्रकटीकरण में जांच करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना और ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न की पर्याप्त सुरक्षा तथा उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।*
3.	न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010 *न्यायिक मानक निर्धारित करने और सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी जज के दुर्व्यवहार या अक्षमता की शिकायतों को निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने और जजों द्वारा परिसंपत्ति और दायित्व की घोषणा का उपबंध करने के लिए*
4.	संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 *उच्च न्यायालयों के जजों, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जजों अथवा कार्यवाहक जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ा कर 65 करना*
5.	पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 *कच्चा तेल उत्पादों की पाइपलाईनों से चोरी और तोड़फोड़ की रोकथाम हेतु उपबंध करने के लिए*
6.	वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011, **लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *वैज्ञानिक नवप्रवर्तन अनुसंधान अकादमी को डिग्रियां प्रदान करने के अधिकारों के साथ एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए*
7.	बीज विधेयक, 2004 *बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता का विनियमन करने और गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुगम बनाने तथा उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए।*

8.	संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 *(i) सहकारी सोसाइटियों के कार्यचालन पर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को न्यूनतम करना ताकि उन्हें एक वास्तविक लोकतांत्रिक और स्वायत दर्जा दिया जा सके* *(ii) सहकारी सोसाइटियों के यथासमय चुनाव, आम सभा की बैठकें और लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए* *(iii) इन संस्थाओं के प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लिए*
9.	नाशक जीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008 *कीटनाशक दवाओं की बिक्री, प्रबंधन, आयात, निर्यात, वितरण और उनके प्रयोग का कारगर रूप से प्रबंधन और विनियमन करने के लिए*
10.	दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 *4 पूर्णकालीक सदस्यों सहित दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन जिनके नाम हैं – अध्यक्ष, सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त), सदस्य-सचिव और 6 अशंकालिक सदस्य – 1 केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि-झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से 1-1 प्रतिनिधि, 3 स्वतंत्र विशेषज्ञ – सिंचाई, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन अथवा ट्रांसमिशन के क्षेत्र से 1 प्रतिनिधि*
11.	चार्टर्ड अकाउण्टेंट (संशोधन) विधेयक, 2010 *तीन संस्थाओं के सदस्यों को सीमित दायित्व भागीदारी 2008 के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी (एल.एल.पी.) फर्म बनाने के लिए*
12.	लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2010 *तीन संस्थाओं के सदस्यों को सिमित दायित्व भागीदारी (एल.एल.पी.) के लिए और संस्था के नाम को भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार से बदलकर भारतीय लागत और प्रबंधन लेखाकार करने के लिए*
13.	कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010 *व्यावसायिक निकायों के लिए एक माध्यम के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी (एल.एल.पी.) को शामिल करने के लिए*
14.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 *पेंशन निधियां स्थापित, विकसित और विनियमित करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और पेंशन निधियों संबंधी योजनाओं में अंशदाताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक सांविधक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) की स्थापना करने के लिए।*
15.	जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 *जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का संशोधन करना (i) पूंजी को पांच करोड़ से बढ़ाकर सौ करोड़ करना (ii) अतिरिक्त वितरण को 95 प्रतिशत से 90 प्रतिशत करने के लिए धारा 28 में संशोधन करना*
16.	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 *नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए*
17.	केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010 *केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2005 का संशोधन करना*
18.	शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010, **लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *जिन विवादों में शिक्षक और अन्य पणधारी शामिल होते हैं, उनके कारगर और शीघ्र न्याय निर्णय के लिए शैक्षिक अधिकरणों की स्थापना करने और उच्च शिक्षा में अनुचित व्यवहार में लिप्त होने के लिए शास्तियों का निर्णय करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए*
19.	प्रौद्योगिकी संस्थान, (संशोधन) विधेयक, 2011, **लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम की परिधि में लाने के लिए*
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011, **लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *(i) अधिनियम के वर्तमान पारंपरिक उपबंधों को मजबूत करने के लिए*

	(□□i) बी.ओ.जी. में लगभग प्रधान केंद्रीय संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए *(iii□□□) उप निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए; और* *(□□iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 में भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का शामिल किया जाना।*
21.	वास्तुविद् (संशोधन) विधेयक, 2010 *अधिनियम के उपबंधों में स्पष्टता लाने और सांविधिक निकायों के बीच टकराव को समाप्त करने के लिए*
22.	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 *डिजीटल वातावरण में प्रतिलिप्यधिकार कार्यों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, संगीत और फिल्म उद्योग की चिन्ताओं की रक्षा करने के लिए, परिचालन संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और किसी कार्य के लेखकों की चिन्ताओं की रक्षा करने के लिए, अधिकार के प्रवर्तन को सुदृढ करने तथा कुछ प्रासंगिक प्रभार आरंभ करने के लिए।*
23.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकातंत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक, 2010 *राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान, संस्थान बंगलौर के नाम से विख्यात संस्थान को एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने और इसके निगमीकरण का उपबंध करने के लिए और उससे जुड़े मामले*
24.	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 *निगम में कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को लागू करने के लिए*
25.	संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2010, **राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए*
26.	विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 *हिंदी विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियिम, 1954 के संशोधन के लिए*
27.	उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009, **लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में** *वाणिज्यिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और इससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए उच्च न्यायालयों में एक वाणिज्यिक खंड के गठन का उपबंध करने के लिए*
28.	संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009 *पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने के लिए*
29.	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक, 2011 *बच्चों को यौन अपशब्द और शोषण से बचाना*
30.	राष्ट्रीय धरोहर स्थल आयोग विधेयक, 2009 *एक संस्थागत तंत्र का उपबंध करने के लिए जो यथासंभव प्रत्ययात्मक ढांचे में धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण का एक संपूर्ण रूख अपनाएगा तथा देश में एक समान विधायी ढांचा और प्रक्रियाओं का उपबंध करने के लिए*
31.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 *(क) "सुविधाहीन वर्ग से संबंध रखने वाले बालक" संबंधी परिभाषा में "अक्षम बालक" को विशिष्ट रूप से शामिल किया जाना और अक्षमताओं के क्षेत्र को बढ़ाना।* *(ख) "आर्थिक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों" के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समितियों संबंधी उपबंधों में संशाधन करना।*

II. पुर:स्थापन, विचार और पारित करने के लिए विधेयक

केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 – **(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)**

III. पुर:स्थापन के लिए विधेयक

क्र.सं.	विधेयकों के नाम
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011
2.	धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011
3.	इलेक्ट्रानिक सेवा वितरण विधेयक, 2011
4.	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011
6.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011
7.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011
8.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011
9.	भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
10.	क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2011
11.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
12.	कंपनी विधेयक, 2011
13.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एजीम बैंक) संशोधन विधेयक, 2011
14.	प्रतिभूति हित और ऋण वसूली प्रवर्तन विधियां (संशोधन) विधेयक, 2011
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक, 2011
16.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011
17.	आयुध (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011
18.	प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण तथा प्रकाशन विधेयक, 2011
19.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011
20.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011
21.	राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011
22.	आणविक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
23.	रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 2011

IV. वित्तीय कार्य

<u>क्रम सं.</u> **विधेयकों के नाम**

1. वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान
2. वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान